सत्यमेव जयते

पंजाब के राज्यपाल

श्री गुलाब चंद कटारिया

द्वारा

विधान सभा

में

दिनांक 21 मार्च, 2025 दिन शुक्रवार

को दिया गया

भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण,

1. मुझे 16वीं पंजाब विधानसभा के 8वें सत्र में इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे वर्तमान बजट सत्र को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विधान सभा का वार्षिक बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वार्षिक बजट केवल प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा नहीं होता बल्कि यह नागरिकों के भलाई के लिए सरकार के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में किया गया विचार-विमर्श पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि की दिशा में अपने शिखर पर पहुंचेगा।

2. मेरी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक चलाए जा रहे हैं। इन क्लीनिकों में कुल 2.98 करोड़ मरीज स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं और अब तक 90 लाख से अधिक डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट किए जा चुके हैं। इन

क्लीनिकों में मरीजों को प्रचलित मार्किट दरों पर 600 करोड़ रुपये मूल्य की दवाइयां तथा 100 करोड़ रुपये मूल्य के डायग्नोस्टिक्स परीक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। इन क्लीनिकों ने राज्य के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च को 1296 करोड़ रुपये तक कम करने में अपना योगदान दिया है।

3. मेरी सरकार सरकारी अस्पतालों में सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद पर 200.00 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार सभी जिला, उप-मंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधा बहुत ही उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मरीजों को उचित मूल्य पर ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 554 निजी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों को भी सूचीबद्ध किया गया है। इस पर होने वाला अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अगले 12 महीनों में इन सेवाओं के चलते पंजाब के मरीजों को लगभग 53 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

4. मेरी सरकार सरकारी अस्पतालों के भवन ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों के भवनों के सुधार के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान 16 सरकारी अस्पतालों में सिविल कार्यों और अग्निशमन प्रणालियां स्थापित करने पर 150.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

5. जिला अस्पताल, बरनाला में एम.सी.एच विंग का निर्माण पूरा हो गया है। जिला अस्पताल फरीदकोट, जिला अस्पताल गुरदासपुर, जिला अस्पताल श्री मुक्तसर साहिब, जिला अस्पताल लुधियाना, उप-मंडल अस्पताल, तलवंडी साबो और उप-मंडल अस्पताल, पट्टी में एम.सी.एच विंग का निर्माण कार्य 54.60 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है। संगरूर जिले के कौहरीयां में 30 बिस्तरों वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चीमा में 30 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल तथा उप-मंडल अस्पताल, धूरी में 80 बिस्तरों वाले एम.सी.एच विंग का निर्माण भी 44.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा होने की उम्मीद है। सिविल अस्पताल बठिंडा और एसबीएस नगर में 50 बिस्तरों वाले

क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी 41.15 करोड़ रुपये की लागत से इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है।

6. पंजाब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 19 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। यह योजना, सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में पात्र लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है, ताकि प्रत्येक नागरिक, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। योजना के अंतर्गत अब तक 88,41,358 ई-कार्ड एक्टिवेट किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 25,31,540 मरीजों का उपचार किया जा चुका है तथा 2609.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

7. दुर्घटना के शिकार लोगों के जीवन और अंगों को बचाने के लिए, मेरी सरकार ने सड़क किनारे दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली चोटों के कारण मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम करने के लिए दिनांक 25.01.2024 को फरिश्ते योजना शुरू की।

अब तक 487 (178 सार्वजनिक और 309 निजी) अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जा चुका है। योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी, 2025 तक कुल 404 लाभार्थियों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और उन्होंने इस योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज कराया है, जिसकी पूर्व-अधिकृत राशि 42.55 लाख रुपये है।

8. वर्तमान में हमारे पास राज्य में 12 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1700 एम.बी.बी.एस सीटें हैं। मेरी सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत होशियारपुर, कपूरथला और मलेरकोटला में 3 नए मेडिकल कॉलेज और राज्य फ़ंड से संगरूर और एस.बी.एस नगर में 2 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

9. मेरी सरकार ने नियमित योग अभ्यास को प्रोत्साहित करने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, तनाव को कम करने तथा अपने नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए "सीएम दी योगशाला" परियोजना शुरू की है। वर्तमान में, पंजाब के सभी जिलों के विभिन्न शहरों में

प्रतिदिन 3,200 योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 1,00,000 लोग लाभान्वित होते हैं।

10. मेरी सरकार "पंजाब सिक्खिया क्रांति" के तहत सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से प्रबंधित, सुरक्षित और संरक्षित कैम्पस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पेस्को के माध्यम से 2042 कैम्पस मैनेजर, 1378 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने स्कूलज़ आफ़ एमिनेंस तथा गर्लज़ स्कूलों में 230 बसों के परिचालन के साथ रियायती परिवहन सुविधा शुरू की है।

11. मेरी सरकार 1970 आई.सी.टी. प्रयोगशालाएं, 7702 स्मार्ट कक्षाएं तथा 19120 स्कूलों में 100 एम.बी.पी.एस स्पीड इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करके सरकारी स्कूलों में हाईटेक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

12. मेरी सरकार विद्यार्थियों को मानसिकता कौशल और संसाधन प्रदान करके उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें सच कर दिखाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती चरण में ही व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर योजना शुरू की

है। इस योजना के अंतर्गत 6700 टीमों के 51,565 विद्यार्थियों का चयन किया गया और उन्हें अपने व्यावसायिक विचारों को वास्तविक कारोबार में परिवर्तित करने के लिए 10.32 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि दी गई।

13. मेरी सरकार ने सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के प्रयास में अतिरिक्त क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर 568.43 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

14. मेरी सरकार स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2644 मास्टर कैडर शिक्षकों को लैक्चरार के पद पर पदोन्नत किया गया है, 424 प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नत किया गया है तथा एक दशक में पहली बार 57 प्रधानाचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

15. मेरी सरकार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए गरीबी रेखा

से ऊपर के वर्ग 1 से 8 तक के 5,83,333 विद्यार्थियों को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए 35.0 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

16. मेरी सरकार ने किसानों, विशेषकर नहरों के अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों को नहर का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। इस प्रयास को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में नहरों के पुनर्वास और लाइनिंग के लिए 79 परियोजनाएं चलाई हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले 30 से 40 वर्षों से बंद या निष्क्रिय पड़ी 77 नहरों को भी बहाल किया गया है, जिनकी लंबाई लगभग 545 किलोमीटर है। इसके अलावा, पिछले 30-40 वर्षों से बंद पड़े लगभग 4200 किलोमीटर लम्बे कुल 16000 जलमार्गों को पुनः स्थापित किया गया है। निरंतर प्रयासों से मेरी सरकार पिछले खरीफ सीजन के दौरान पिछले 5 वर्षों की तुलना में 12% से अधिक अतिरिक्त जल का उपयोग करने में सफल रही है।

17. मेरी सरकार ने बाढ़ के मौसम में नुकसान को रोकने के लिए 99 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा और नालों की

सफाई के कार्य करवाए हैं। विभिन्न जिलों में लगभग 3000 किलोमीटर नालों की सफाई के कार्य और लगभग 46 बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए हैं। इसके अलावा, मेरी सरकार ने राज्य आपदा न्यूनीकरण फ़ंड के अंतर्गत बाढ़ न्यूनीकरण के लिए 60 कार्यों हेतु लगभग 70 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। मेरी सरकार ने जालंधर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जालंधर शहर में काला सिंघा नाले की लाइनिंग का कार्य भी शुरू किया है, जिसकी लागत 34.00 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देते हुए मेरी सरकार ने "रावी नदी पर भारत-पाक सीमा पर कटाव की समस्या से निपटने तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे संरक्षण कार्यों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्यों हेतु समेकित प्रोजेक्ट" के लिए अतिरिक्त 3.74 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

18. मेरी सरकार के सतत प्रयासों से, 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित शाहपुर कंडी बांध परियोजना अंततः वास्तविक रूप ले रही है। जलाशय को भरने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से 206 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 1042 मेगा यूनिट हाइड्रो-इलैक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी और 37,173

हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा होगी, साथ ही यू.बी.डी.सी प्रणाली के तहत अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट जिलों में 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की गहन सिंचाई होगी। पाकिस्तान की ओर व्यर्थ जाने वाले पानी को भी रोका जाएगा।

19. इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने "मनरेगा की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए उसके साथ समन्वय करके विभिन्न कार्यों का निर्माण" प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अलावा, मेरी सरकार ने मनरेगा फ़ंडों का उपयोग करते हुए विभिन्न बाढ़ सुरक्षा कार्यों, नहरों की सफाई, नहरों की लाइनिंग, नालों की सफाई और जलमार्गों की मरम्मत के लिए 270 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है।

20. मेरी सरकार ने केन्द्रीय पूल के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद के लिए सफलतापूर्वक खरीद कार्य किया है। रबी और खरीफ सीजन के दौरान क्रमशः 121.31 लाख टन गेहूं और 173.58 लाख टन धान खरीदा गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के 68,630 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों

में किया गया। राज्य ने 2024-25 के दौरान केंद्रीय पूल में 45% गेहूं का बड़ा योगदान दिया है।

21. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 14,400 ई-पी.ओ.एस किट और इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू खरीदे हैं तथा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान को समर्पित ई-पी.ओ.एस किट और इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू से लैस किया है।

22. प्रदेश में खाद्यान्नों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भण्डारण को सुनिश्चित करने के लिए 10 वर्ष की गारंटी के आधार पर 9 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, जिसमें से 2 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु सफल बोलीदाताओं को अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, आगामी आर.एम.एस 2025-26 के दौरान गेहूं का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए 35 एल.एम.टी वैज्ञानिक सी.ए.पी (कवर और प्लिंथ) के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।

23. कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट के दौरान, पंजाब राज्य और इसके मेहनती किसानों ने हरित क्रांति लाने में अग्रणी भूमिका निभाई और पिछले पांच दशकों से भारत की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में लगातार योगदान दिया है। पंजाब में लगभग 42 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है, जो देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 3% है, लेकिन पंजाब कुल उत्पादन का लगभग 18% गेहूं, 11% चावल और 4% कपास पैदा करता है। पंजाब का मंडी ढांचा भारत में सबसे मजबूत है और 2023-24 के दौरान पंजाब राज्य ने केंद्रीय अनाज भंडार में क्रमशः धान और गेहूं का लगभग 24% और 50.4% योगदान दिया है।

24. मेरी सरकार ने चावल की सीधी बुवाई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की है। खरीफ 2024 के दौरान, डी.एस.आर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई, जबकि खरीफ 2023 के दौरान 1.70 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.8% अधिक है।

25. वर्ष 2024 के दौरान 6.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की खेती की गई है, जबकि खरीफ 2023 के दौरान 5.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% अधिक है। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानक का बासमती निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए पंजाब सरकार ने बासमती पर इस्तेमाल होने वाले 10 कृषि कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि विभाग ने कीटनाशक अवशेष मुक्त बासमती उत्पादन के लिए अमृतसर जिले के चौगावां ब्लॉक में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

26. मेरी सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए किसान समूहों/पंचायतों को 80% सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक पराली प्रबंधन के लिए कुल 1,46,500 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में धान की पराली में आग लगाने की घटनाओं में 70% की कमी आई है।

27. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा मक्का के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पी.ए.यू, लुधियाना द्वारा

प्रमाणित एवं अनुशंसित मक्का के बीजों की हाइब्रिड किस्मों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 2.30 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। इसके अलावा, राज्य में 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का प्रदर्शनी भी लगाई गई है। किसानों को मक्का के बीज और अन्य इनपुट जैसे खाद, कीटनाशक आदि हेतु 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

28. पंजाब सरकार ने पंजाब के पर्यावरण, संस्कृति और फसलों पर आधारित कृषि नीति तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिससे टिकाऊ कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि नीति का मसौदा सभी हितधारकों, किसान/श्रमिक संघों को भेज दिया गया है तथा उनसे उनकी बहुमूल्य राय मांगी गई है।

29. मेरी सरकार छोटे और सीमांत किसानों को खादों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्रिय रही है। उच्च सब्सिडी के कारण देश भर में खादों की कमी के बावजूद, मेरी सरकार ने मार्कफेड की खादों की पूर्व-व्यवस्था और राज्य भर में उनके

आवागमन की कड़ी निगरानी की रणनीति द्वारा समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया। वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी समितियों से जुड़े छोटे एवं सीमांत किसानों को कुल 13,82,769 मीट्रिक टन यूरिया और 3,17,828 मीट्रिक टन डी.ए.पी. वितरित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कृषि गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रहें।

30. मेरी सरकार पंजाब राज्य में डेयरी प्रोसेसिंग के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और एन.पी.डी.डी योजना (जे.आई.सी.ए ऋण सहायता) के तहत 325 करोड़ रुपये की मोहाली डेयरी विस्तार परियोजना स्थापित करने के लिए मिल्कफेड की मदद कर रही है और इसी तरह, नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आर.आई.डी.एफ योजना के तहत 112 करोड़ रुपये की लागत से श्री अमृतसर साहिब डेयरी के विस्तार प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन दोनों प्रोजेक्टों से मोहाली, रोपड़, श्री फतेहगढ़ साहिब, श्री अमृतसर साहिब और तरनतारन जिलों के किसानों को लाभ होगा। इस के अलावा, मिल्कफेड पंजाब ने वित्त वर्ष 2024-25 में प्रतिदिन 21.50 लाख लीटर दूध खरीदा है, जबकि

तीन साल पहले औसतन प्रतिदिन 19.16 लाख लीटर दूध खरीदा जाता था। इस प्रकार, अतिरिक्त दूध खरीदकर, मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 370 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि डाल रही है।

31. मेरी सरकार, किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पंजाब में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादकों को पिछले बकाये का भुगतान करने तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सक्रिय रही है। पेराई वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश की 09 सहकारी चीनी मिलों द्वारा 195.67 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई। सहकारी चीनी मिलों से जुड़े 24043 गन्ना उत्पादकों की 764.99 करोड़ रुपये की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया।

32. मेरी सरकार ने 296.14 करोड़ रुपये की लागत से बटाला सहकारी चीनी मिल में रिफ़ाइंड और औषधीय चीनी उत्पादन की सुविधा के साथ 14 मेगावाट सह-उत्पादन और रिफाइनरी के साथ 3500 टी.सी.डी की नई चीनी मिल परियोजना स्थापित की है, जिसे 5000 टी.सी.डी तक बढ़ाया जा सकता है। इस नई चीनी मिल में पेराई सत्र 2024-25 शुरू हो गया

है। गुरदासपुर सहकारी मिल में 402.00 करोड़ रुपये की लागत से 28 मेगावाट सह-उत्पादन के साथ 5000 टी.सी.डी का एक और नया चीनी प्लांट लगाया जा रहा है। प्रोजेक्ट साईट पर कार्य पूरा होने के कगार पर है और व्यावसायिक उत्पादन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

33. मार्कफेड के सोहना ब्रांड की वृद्धि उल्लेखनीय रही है और सोहना उत्पादों का कारोबार लगभग 250 करोड़ रुपये से बढ़कर 350 करोड़ रुपये हो गया है।

34. मेरी सरकार पंजाब के सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और हर नागरिक को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित हैं।

35. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार की ईमानदार मंशा के कारण, हमने 2.33 से 2.76 रुपये प्रति यूनिट की औसत दर पर 3704 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 3.22 से 3.28 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 900 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा हासिल

की। इसके अलावा, पूरे पंजाब में छतों पर सौर पैनल लगाकर 430 मेगावाट हरित ऊर्जा को शामिल किया गया है।

36. पछवाड़ा से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले से संयंत्र के संचालन में सुधार हुआ है और पी.एस.पी.सी.एल थर्मल पावर स्टेशनों को अब उत्तम बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है तथा उनके पास हमेशा 27 दिनों से अधिक समय के लिए कोयले का स्टॉक रहता है। इसके अलावा, पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले की उपलब्धता के कारण, राज्य के स्वामित्व वाले थर्मल प्लांटों में 2023-24 से किसी भी आयातित कोयले का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे लगभग 600 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

37. वर्ष 2024-25 के दौरान, पंजाब ने 29.06.2024 को 16,058 मेगावाट की अपनी अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग को पूरा किया है। कुल मिलाकर, 21.07.2024 को एक दिन के दौरान रिकॉर्ड 3666 लाख यूनिट की ऊर्जा मांग को पूरा किया गया।

38. मेरी सरकार ने धान के मौसम के दौरान घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य उपभोक्ताओं पर बिना कोई बिजली कटौती किए कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिसके परिणामस्वरूप धान की बंपर फसल हुई।

39. जीवन स्तर में सुधार के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। मेरी सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली योजना लागू की है। इससे लगभग 70 लाख यानी 90% परिवारों को लाभ मिला है और उन्हें एक बिलिंग चक्र में कोई बिल नहीं मिला है। इसके अलावा, सभी कृषि उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली मिल रही है। मेरी सरकार ने राज्य के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को 5.667 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

40. मेरी सरकार ने रोपड़ में एक नया 400 के.वी सब-स्टेशन, विभिन्न स्थानों पर 16 नए 66 केवी सब-स्टेशन चालू करके

तथा गुरदासपुर में मौजूदा 132 केवी सब-स्टेशन को 220 केवी में अपग्रेड करके ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को अपग्रेड किया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

41. मेरी सरकार ने अक्टूबर, 2024 तक कुल 6830.50 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं। कृषि क्षेत्र में 17600 सौर पंप चालू किए गए हैं। गांवों में 1,12,260 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

42. पिछले एक वर्ष में मेरी सरकार ने 1468 प्लेसमेंट कैम्पों/जॉब मेलों/स्वरोजगार शिविरों के माध्यम से 85,248 अभ्यर्थियों को नौकरी/स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई है।

43. पिछले एक वर्ष के दौरान महाराजा रणजीत सिंह आर्मड फ़ोर्सिज़ प्रेपरेटरी इंस्टीच्यूट, माई भागो आर्मड फ़ोर्सिज़ प्रेपरेटरी इंस्टीच्यूट और पंजाब युवा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र द्वारा 8614 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 1129 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई।

44. योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान करने के प्रयास को जारी रखते हुए, मेरी सरकार ने भर्ती में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ-साथ दक्षता भी सुनिश्चित की है। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2022 से अब तक नियमित भर्ती के अंतर्गत कुल 51,655 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसमें पंजाब के कई सक्षम युवा, जो पहले विदेश जाने का विकल्प चुनते थे, अब पंजाब सरकार की सेवा में शामिल हो रहे हैं।

45. मेरी सरकार ने खेलों के क्षेत्र में पंजाब के गौरव को पुनः बहाल करने के लिए 2023 में राज्य की नई खेल नीति अधिसूचित की है। पूरे राज्य में हर घर तक आसान पहुंच के साथ खेल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, नई खेल नीति के तहत इस वर्ष 1000 खेल नर्सरियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए तथा सभी गांवों में खेल के मैदान तैयार करने के लिए खेल विभाग का बजट पिछले वर्ष के 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 850 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

46. मेरी सरकार ने 2024-25 में नई खेल नीति के अंतर्गत सेंटर आफ़ एक्सिलेंस, नर्सरियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी के अंतर्गत 400 से अधिक प्रशिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

47. नई खेल नीति के तहत खेल नर्सरियों में कुल 1000 पदक विजेता खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। खेल नर्सरियां स्थापित होने के बाद 60,000 उभरते खिलाड़ियों को पोषण और साजो-सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्य के युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए माहौल तैयार होगा।

48. मेरी सरकार ने "खेडां वतन पंजाब दीयां, 2024" के सीज़न-3 का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कई खेल शामिल थे, जिसकी लागत 30.00 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष भी खेडां वतन पंजाब दीयां के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पिछले वर्ष सभी आयु समूहों से 4.5 लाख लोगों की भागीदारी देखी गई थी।

49. मेरी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी के लिए 30 खिलाड़ियों को 3.44 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाग लेने वाले या पदक जीतने वाले 3996 खिलाड़ियों को 12.66 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किए हैं। खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल कोचिंग आदि क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय, पटियाला को वर्ष 2024-25 के लिए 34.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

50. मेरी सरकार राज्य में उद्योग को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मौजूदा और नई इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास नीति 2022 को अधिसूचित किया गया था ताकि एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क, स्टांप शुल्क, बाजार शुल्क, सीएलयू/ईडीसी में छूट, वित्त, प्रौद्योगिकी और विपणन के क्षेत्र में एम.एस.एम.ई को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। पिछली एवं वर्तमान औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत मार्च 2022 से अब तक लगभग 670 इकाइयों को 8,910

करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक राज्य ने बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 7,250 करोड़ रुपये जारी किए हैं और वित्त विभाग से बिजली टैरिफ सब्सिडी के रूप में 3335.42 करोड़ रुपये की मांग की है।

51. अपने ईमानदार प्रयासों से मेरी सरकार को मार्च 2022 से अब तक 5,986 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 96,836 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा लगभग 4,20,030 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार प्रत्येक स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 3 लाख रुपये प्रदान कर रही है और अब तक 2022 तक 123 स्टार्टअप को 3.69 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

52. मेरी सरकार ने पी.एस.आई.ई.सी. के डिफॉल्टर प्लॉट धारकों से बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल लागत की लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, सभी संबंधित डिफॉल्टरों को 31.12.2025 तक अपने बकाए का भुगतान करना होगा,

जिसमें 100% दंडात्मक ब्याज माफ किया जाएगा और लंबित बकाए पर 8% साधारण ब्याज लगाया जाएगा। इससे उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

53. पिछले एक वर्ष में मेरी सरकार ने चार सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर आफ़ एक्सिलेंस में अपग्रेड किया है तथा सात सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिक मशीनरी से सुसज्जित किया है, जिससे राज्य के युवाओं को लाभ मिल रहा है।

54. उद्योग-अकादमिक अंतर को पाटने के लिए, मेरी सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग-उन्मुख कोर्स शुरू किए हैं। सत्र 2024-25 में सरकारी आई.टी.आई में 5,000 नई सीटें शामिल की गई हैं और 06 सरकारी पॉलिटेक्निकों में 510 नई सीटें शामिल करते हुए नए कोर्स शुरू किए गए हैं।

55. मेरी सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के

अनुरूप, हम 2,174 करोड़ रुपये के निवेश से 15 बड़ी बहु-ग्राम सतही जल आपूर्ति योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिससे 25 लाख ग्रामीण निवासियों को लाभ मिलेगा। ये प्रोजेक्ट उन्नत चरणों में हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इनके पूरी तरह शुरू हो जाने की उम्मीद है।

56. ग्रामीण जल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 117.58 करोड़ रुपये की लागत वाली और 104 गांवों को कवर करने वाली 82 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं और एक सीवरेज योजना को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 में 159.95 करोड़ रुपये के निवेश से 176 गांवों को लाभान्वित करने वाली 144 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं विस्तार और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में हैं।

57. खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) राज्य का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त करने और बनाए रखने के बाद, मेरी सरकार अब राज्य के प्रत्येक गांव के लिए व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करके ओ.डी.एफ प्लस (मॉडल) दर्जा हासिल

करने की ओर बढ़ रही है। अब तक 1,747 गांवों को ओ.डी.एफ प्लस (मॉडल) घोषित किया जा चुका है, जो स्थायी स्वच्छता कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

58. ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता के प्रति मेरी सरकार के प्रयास राज्य के विभिन्न गांवों में तालाबों के जीर्णोद्धार में स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब तक 1087 कार्य पूरे हो चुके हैं तथा 482 कार्य प्रगति पर हैं।

59. ग्रामीण आजीविका को और बेहतर बनाने के अपने प्रयास में, मेरी सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की है। पंजाब ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.58 लाख विकास कार्य शुरू किए हैं, जिन पर लगभग कुल 1333 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इससे रोज़गार के अवसर देते हुए 299 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिससे 8.17 लाख परिवारों को आवश्यक जीविका प्राप्त हुई है। इस योजना के अंतर्गत, मेरी सरकार ने विभिन्न गांवों में खेल के मैदान विकसित करने की पहल की

है, जो हमारे युवाओं के मनोरंजन और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 3291 खेल मैदान विकसित किये जा चुके हैं तथा 1548 खेल मैदानों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में राज्य भर में 95 लाख से अधिक पेड़ लगा कर पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

60. सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को सफलतापूर्वक लागू करने से झलकती है। हमने 39,660 के लक्ष्य के मुकाबले 38,478 मकानों का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, तथा 97% की प्रभावशाली सफलता दर हासिल की है। 42,562 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 31,468 आवासों को मंजूरी दी गई है, जो 70% आवासों के निर्माण की उपलब्धि है, तथा शेष लाभार्थियों को भी कवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

61. मेरी सरकार ने ग्रामीण आजीविका को और बेहतर बनाने के प्रयास में राज्य ग्रामीण आजीविका योजना के अंतर्गत

महत्वपूर्ण सुधार किया है। 545311 परिवारों को शामिल करते हुए कुल 54326 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। 31.12.2024 तक 3851 ग्राम संगठन और 148 क्लस्टर स्तरीय संघ बनाए गए हैं। 7589 स्वयं सहायता समूहों को 94.35 करोड़ रुपये का ऋण मिला है। स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तहत 455 लाभार्थियों को 94 लाख रुपये वितरित किए गए हैं, प्रधानमंत्री फ़ार्मलाइज़ेशन आफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग के तहत 4304 लाभार्थियों को 2.14 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। पहल प्रोजेक्ट के तहत 3600 स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा 7 लाख सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म सिली जाएंगी।

62. मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि राजस्व सेवाएं आम आदमी को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। एक व्हाट्सएप शिकायत केंद्र स्थापित किया गया है। लोग व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इन शिकायतों का 21 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

63. मेरी सरकार ने जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सब-डिविजनल कॉम्प्लेक्स, तहसीलों, उप-तहसीलों और पटवार कार्य केन्द्रों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 248 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

64. आतंकवाद प्रभावित परिवारों तथा 1984 के दंगों से प्रभावित परिवारों की भलाई के लिए राज्य में लाभार्थियों को 34.6 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई।

65. स्वर्ण मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में लंगर के लिए खरीदे गए सामान पर जीएसटी की भरपाई के लिए मेरी सरकार ने डी.सी. अमृतसर को 2.7 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

66. मेरी सरकार ने जिला फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद स्थित रोज़ा शरीफ के रखरखाव के लिए 5 लाख रुपए की राशि आवंटित की है।

67. मेरी सरकार ने नागरिकों की मांग पर घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज या “भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार” नामक एक नई योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत, शुरुआत में 43 नागरिक सेवाओं की पहचान की गई थी, जो लेन-देन का 99% से अधिक हिस्सा था। अब, सेवा केंद्रों की सभी सेवाएँ, जहाँ सेवा केंद्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है, इस योजना के तहत शुरू की गई हैं। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से 406 सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। 1 लाख से अधिक नागरिकों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है।

68. इसके अलावा, निर्बाध और पारदर्शी सेवा प्रदानगी तथा भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टालरेंस की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मेरी सरकार ने पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है। अब नागरिकों को हस्ताक्षर और रिपोर्ट के लिए इन अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके आवेदनों की तसदीक ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएगी। इस प्रकार, सरकार ने उन नागरिकों को सशक्त बनाया है, जिन्हें अपने घर पर या किसी भी सेवा केंद्र पर सेवाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। इसकी शुरूआत के बाद से, सरपंचों, नंबरदारों

और एमसी के माध्यम से 1175 आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है।

69. मेरी सरकार ने विधानसभा को डिजिटल रूप से काम करने और इसकी दक्षता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद की है। पंजाब विधानसभा में सितंबर 2023 से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पेपरलेस विधानसभा में बदलाव से अधिक दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित हुई है। सितंबर 2023 के बाद विधानसभा के सत्र पेपरलेस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं।

70. मेरी सरकार ने, 1,367 पशु चिकित्सालयों, 1489 पशु औषधालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पशुपालकों को 4.15 मिलियन ओ.पी.डी. सेवाएं प्रदान की हैं, तथा राज्य के पशुओं को घातक बीमारियों से बचाने के लिए 12.85 मिलियन टीके लगाए हैं। एल.एस.डी. वैक्सीन की 24.28 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं और विभाग ने अगले वर्ष के लिए 25 लाख खुराकें खरीदने की योजना बनाई है। एफ.एम.डी. वैक्सीन की 63.22 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं और विभाग

ने अगले वर्ष के लिए 65 लाख खुराकें खरीदने की योजना बनाई है।

71. वर्ष 2025-26 के दौरान 30 लाख कृत्रिम गर्भाधान खुराकें देने के लक्ष्य के साथ, घर-घर जाकर 2.28 मिलियन कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं। पिछले वर्ष उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली मादा बछड़ियों के उत्पादन के लिए फ्रोजन सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन की 1,75,000 खुराकें खरीदी गई हैं, 50,000 खुराकों के लिए ऑर्डर दिया गया है तथा सेक्स्ड सीमेन की अतिरिक्त 1,50,000 खुराकें खरीदने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

72. मेरी सरकार मछली पालन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मछली विभाग ने 8524 व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया है तथा सरकारी मछली फार्मों में 147.74 लाख मछली बीज उत्पादित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 135 लाभार्थियों को कुल 452.00 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है, जिससे मछली और झींगा पालन के विस्तार, मछली परिवहन और नवीन जलीय कृषि

प्रणालियों जैसे री-सर्कुलेटरी एक्काकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक कल्चर सिस्टम और मछली कियोस्क आदि जैसे विभिन्न प्रोजेक्टों को समर्थन मिला है। उपभोक्ताओं को स्वच्छ मछली उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जिला पटियाला के गांव घलौड़ी में एक खुदरा मछली बाजार का भी उद्घाटन किया गया है।

73. राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में लगभग 3097 नई डेयरी इकाइयां स्थापित की गई हैं।

74. मेरी सरकार के केंद्रित प्रयासों ने राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को स्थिरता और सतत विकास की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वयं-कर राजस्व में दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करना रही है, जो इसकी प्रभावी रणनीतियों और उपलब्धियों को दर्शाता है। प्रमुख उपलब्धियों में स्टाम्प और पंजीकरण में 35% की वृद्धि, वाहनों पर करों में 15% की वृद्धि, राज्य उत्पाद शुल्क में 14% की वृद्धि और राज्य जीएसटी में 13% की वृद्धि (फरवरी 2025 तक) शामिल है।

75. 16वें वित्त आयोग के सामने एक विस्तृत एवं सावधानीपूर्वक तैयार किया गया ज्ञापन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, जो पारदर्शिता एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि राज्य के विभिन्न विभागों से डेटा के व्यापक संग्रह और संकलन के माध्यम से संभव हुई, जिससे राज्य की राजकोषीय स्थिति का व्यापक और सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देते हुए, राज्य को आयोग के सम्मानित सदस्यों की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ, जिससे सहयोग और पारस्परिक समझ की भावना को बढ़ावा मिला।

76. सुरक्षित और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई-वाउचर, गैर-कोषागार लेखा मॉड्यूल और एस.एन.ए. स्पर्श मॉड्यूल विकसित और लागू किए गए हैं तथा बिलों के प्रमाणीकरण के लिए ई-साइन सुविधा भी शामिल की गई है।

77. इसके अलावा, पेंशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए, इस वर्ष के दौरान आई.एच.आर.एम.एस में पेंशन संशोधन मॉड्यूल और पेंशन सेवा पोर्टल नामक एक अलग पोर्टल शुरू किया गया है।

78. मेरी सरकार ने पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम के अंतर्गत राज्य खरीद पोर्टल शुरू किया है, जिससे विभागों को अपनी वार्षिक खरीद योजनाएं अपलोड करने में सुविधा होगी। यह पहल हितधारकों को आगामी प्रोजेक्टों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है तथा सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, खरीद योजनाओं को अपलोड करने से विभागों में बेहतर योजनाबंदी, समन्वय और संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होता है।

79. मेरी सरकार ने 25 फरवरी को अत्यंत दृढ़ संकल्प एवं केंद्रित तरीके से नशीले पदार्थों के विरुद्ध युद्ध (युद्ध नशियां विरुद्ध) की शुरूआत जैसी रणनीतिक पहल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध अपनी लड़ाई तेज कर दी है। इस दृढ़ अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित की गई है। इस पूरे गिरोह के आर्थिक तानेबाने को तोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजाब से नशे की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए राज्य सरकार के दृढ़ निश्चय का संदेश देने के लिए नशा तस्करों की कई संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। स्पेशल

टास्क फोर्स (एस.टी.एफ) को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ) के रूप में पुनर्गठित और मजबूत किया गया है, जिसकी स्थापना मादक द्रव्य कानूनों को लागू करने, पीड़ितों के पुनर्वास और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए की गई थी। लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य भर में 33,079 जन जागरूकता बैठकें आयोजित की गईं और मात्र चार महीनों में 19,523 ग्राम रक्षा समितियां बनाई गईं। नशीली दवाओं से संबंधित डेटा, संचार और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष खुफिया और तकनीकी इकाई भी स्थापित की गई है, जिससे एएनटीएफ की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि हुई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और फील्ड इकाइयों ने संगठित अपराध से निपटने में उल्लेखनीय प्रगति की है, 1,588 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 13 गैंगस्टरों को निष्प्रभावी किया है, 571 आपराधिक गिरोहों का भंडाफोड़ किया है, तथा अपराधों में प्रयुक्त 1,477 हथियार और 327 वाहन बरामद किए हैं।

80. पंजाब के लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मेरी सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव

प्रशासनिक और कानूनी उपाय किए हैं। मेरी सरकार ने काउंटर-इंटेलिजेंस, साइबर अपराध की रोकथाम और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1 जनवरी से 28 नवंबर, 2024 तक पंजाब पुलिस ने नौ आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप 59 गिरफ्तारियां हुई हैं और हथियार बरामद हुए हैं।

81. पंजाब राज्य साइबर अपराध डिवीजन साइबर खतरों से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें पंजाब में 28 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करना, 24x7 सोशल मीडिया निगरानी और साइबर मित्तर चैटबॉट जैसी पहलकदमियां शामिल हैं। 2024 में, 6,000 से अधिक गैरकानूनी पोस्ट हटा दिए गए, जबकि साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन (1930) ने 1500 से अधिक दैनिक कॉल्ज़ सुने, जिससे 797.18 करोड़ रुपये का नुकसान रोका गया और पीड़ितों को 719.03 करोड़ रुपये वापस किए गए। जागरूकता अभियान और 885 पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण ने साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों को और मजबूत बनाया।

82. मेरी सरकार सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। 2023 में, 6,269 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 4,829 मौतें हुईं और 3,206 घायल हुए। 30 सितंबर, 2024 तक, दुर्घटनाएँ घटकर 4,258 रह गईं, जिनमें 3,264 मौतें और 2,281 लोग घायल हुए। जागरूकता बढ़ाने के लिए 2023 में, ट्रैफ़िक एजुकेशन सैल ने स्कूलों, कॉलेजों और परिवहन केंद्रों में 11,369 और 2024 में 8,549 सेमिनार आयोजित किए। स्कूली पाठ्यक्रम में ट्रैफ़िक एजुकेशन शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।

83. पंजाब में फरवरी 2019 से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डायल-112 चालू है, जो संकट की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करती है। निर्भया फंड से 92.85 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस प्रणाली में मोहाली में एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर और 27 जिला तालमेल केंद्र शामिल हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया का विस्तार जारी रखा है।

84. मेरी सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की भलाई को उच्च प्राथमिकता देती है। शहर आर्थिक विकास के वास्तविक इंजन भी हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रयास शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और राज्य के शहरों के निवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है।

85. इस वर्ष 5 नगर निगमों सहित 49 शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी) के चुनाव हुए हैं और मुझे विश्वास है कि नव निर्वाचित पार्षद अपने-अपने मेयरों और अध्यक्षों के साथ मिलकर हमारे शहरों के समग्र सुधार और अच्छे शहरी प्रशासन के लिए साथ मिल कर कार्य करेंगे।

86. घटते भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए अमृतसर में 784 करोड़ रूपये की लागत वाले 440 एम.एल.डी क्षमता वाले सतही जल आधारित जल उपचार प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। लुधियाना में, विश्व बैंक- ए.आई.आई.बी द्वारा वित्तपोषित 1546 करोड़ रुपये की लागत से 580 एम.एल.डी क्षमता वाले जल उपचार प्लांट का निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था। जालंधर और पटियाला में भी बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य के 84 शहरों को भी 2246

करोड़ रुपये की लागत वाली सतही जल आपूर्ति योजनाओं के तहत शामिल किया जा रहा है। 24 शहरों में कार्यों का टेंडर हो चुका है जबकि अन्य कार्य टेंडरिंग के विभिन्न चरणों में हैं।

87. स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने और जल प्रदूषण को कम करने के लिए मेरी सरकार राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापित क्षमता को 376 एम.एल.डी तक बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसमें से 174 एम.एल.डी की क्षमता वाले 42 एस.टी.पी वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, जिन पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत आएगी और ये आने वाले 1-2 वर्षों में पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा, 250 करोड़ रुपये की लागत से 20 और शहरों को पाइप्ड सीवरेज से कवर किया जा रहा है। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के लिए 39.55 करोड़ रुपये की लागत से 730 मशीनें खरीदी हैं।

88. राज्य के बड़े शहरों में ज़ीरो एमिशन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए, मेरी सरकार आने वाले महीनों में प्रमुख शहरों अर्थात् अमृतसर

(100), जालंधर (97), लुधियाना (100) और पटियाला (50) में 347 ई-बसें शुरू करेगी। इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और परिवहन के निजी साधनों पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, मेरी सरकार ने चंडीगढ़ के ट्राइ-सिटी के हिस्से के रूप में एस.ए.एस नगर (मोहाली) क्लस्टर में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है।

89. राज्य के शहरी स्थानीय निकाय ठोस कचरे को बेहतर ढंग से हर घर जा कर इक्ट्ठा करने और इसके पृथक्करण और प्रोसेसिंग के साथ-साथ पुराने कचरे के निपटारे की दिशा में भी काम कर रहे हैं। पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, राही योजना के तहत लक्षित 1200 पुराने डीजल ऑटो-रिक्शा के स्थान पर नए इलेक्ट्रिक ऑटो लाए गए हैं। इसके अलावा, शहर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90% सब्सिडीयुक्त मूल्य पर 200 पिंक ई-ऑटो भी दिए गए हैं।

90. मेरी सरकार सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को मासिक भत्ते के स्थान पर 27.08.2024 से एकमुश्त ग्रांट देने

की नीति लाई है तथा युद्ध जागीर लाभार्थियों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता को दिनांक 08.10.2024 से 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये करने के लिए "दा ईस्ट पंजाब वार अवार्ड एक्ट, 1945" में संशोधन किया है।

91. राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार द्वारा विभिन्न त्यौहारों और मेलों को मनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है। श्री मुक्तसर साहिब में तीज महोत्सव, शहीद भगत सिंह नगर में इंकलाब महोत्सव, चंडीगढ़ में सैन्य साहित्य महोत्सव, पटियाला में विरासत महोत्सव स्थानीय लोगों द्वारा बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया।

92. मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार ने 32.78 करोड़ रुपये की लागत से राम तीर्थ स्थल, अमृतसर में भगवान वाल्मीकि पैनोरमा नामक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना की है, जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के जीवन और योगदान को दर्शाया गया है।

93. मेरी सरकार ने राज्य के पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से आने वाले वित्तीय वर्ष में हुसैनीवाला बॉर्डर और श्री आनंदपुर साहिब, रूपनगर में प्रत्येक पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रोजेक्ट की योजना तैयार की है।

94. मेरी सरकार ने आदमपुर में 154 करोड़ रुपये की लागत से एक नए अत्याधुनिक हवाई टर्मिनल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नए टर्मिनल ने आगमन और प्रस्थान के लिए 150 यात्रियों तक की यात्री क्षमता बढ़ा दी है और अब यह पूरी तरह से कार्यशील है। हिंडन (गाजियाबाद), नांदेड़ और बेंगलुरु सहित प्रमुख स्थलों के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं।

95. हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, अंतरिम टर्मिनल भवन का 90% काम पहले ही पूरा हो चुका है। मेरी सरकार ने टर्मिनल और सड़क संपर्क के निर्माण में 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पंजाब विधानसभा ने हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव की सिफारिश भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजी है। इस हवाई अड्डे के जून 2025 तक कार्यशील होने की

उम्मीद है और यह क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बेहतर बनाने और हवाई संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

96. मेरी सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए पांच पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित की हैं। इससे पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी तथा अनुपयुक्त वाहनों को सड़क से हटाया जा सकेगा।

97. मेरी सरकार नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट आदि से संबंधित 50 प्रकार की स्मार्ट सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान कर रही है। आठ और सेवाएं लागूकरण के उन्नत चरण में हैं। वाहन की फिटनेस जांच ऑनलाइन मोड के माध्यम से जियो-टैगिंग के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चित्रों के साथ की जाती है। विभाग द्वारा ई-चालान मशीनों की व्यवस्था की गई है और यूपीआई/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से मौके पर ही कंपाउंडिंग फ़ीस का भुगतान किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की डिलीवरी घर-घर जाकर की जा रही है।

98. मेरी सरकार मौजूदा सड़कों को अपग्रेड करके, नई सड़कों की योजनाएं बना कर और छूटे हुए संपर्क मार्गों की पहचान करते

हुए अपने नागरिकों को एक अच्छा सड़क नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत, 2579 किलोमीटर योजना सड़कों के निर्माण/अपग्रेडेशन पर 2097 करोड़ रुपये और 136 नए और 29 निर्माणाधीन पुलों के निर्माण पर 967 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसी तरह मेरी सरकार ने 1298 किलोमीटर लंबी सड़कों के अपग्रेडेशन पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

99. राष्ट्रीय राजमार्गों की 70 किलोमीटर लंबी सड़कों को 300 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड करने की योजना है।

100. मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। हमने पंजाब के लोगों के लिए नागरिक अनुकूल और पारदर्शी शासन का वादा किया था। इसके अनुसरण में, राज्य विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब ने 16-03-2022 से 28-02-2025 की अवधि के दौरान पी.सी अधिनियम 1988 (संशोधित) 2018 के तहत 485 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी

व्यक्तियों के खिलाफ 359 मामले दर्ज किए हैं, जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत आर्थिक अपराधों से संबंधित 386 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 957 सरकारी अधिकारी/विभिन्न स्तरों के कर्मचारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं। राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने इन मामलों में 826 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 132 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

101. मेरी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया है, जिससे उन्हें बिना एन.ओ.सी. प्राप्त किए अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने का मौका दिया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2025 थी, जिसे जनता की मांग पर बढ़ाकर अब 31 अगस्त, 2025 कर दिया गया है। साथ ही, अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में एक और संशोधन करके अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले प्रमोटर की सजा और जुर्माने को बढ़ा दिया गया है।

102. मेरी सरकार ने उन प्लॉट धारकों को अवसर प्रदान करते हुए एमनेस्टी पॉलिसी-2025 शुरू की है जो अपनी बकाया किश्तें जमा नहीं कर पाए या निर्धारित समय अवधि में निर्माण पूरा नहीं कर पाए या नॉन कंस्ट्रक्शन फीस जमा नहीं कर पाए। ऐसे आवंटी अब बिना किसी जुर्माने के अपनी बकाया राशि को योजना ब्याज सहित एकमुश्त जमा कर सकते हैं। इस के साथ ही, नॉन कंस्ट्रक्शन चार्ज की बकाया राशि का 50% माफ कर दिया गया है।

103. मेरी सरकार पंजाब राज्य में शहरों/कस्बों के व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान/विकास योजनाएं तैयार कर रही है। अब तक हमने राज्य के 214 शहरों को कवर करते हुए 117 स्थानीय नियोजन क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। 24 और स्थानीय नियोजन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है।

104. नागरिकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए, विभाग ने 1043 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं पूरी की हैं और नई परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे मौजूदा शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति को लेआउट

प्लान, बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी के लाइसेंस की मंजूरी के साथ मिला दिया गया है। इससे निर्माण परमिट जारी करने का समय कम हो गया है जिससे निवेशक कम से कम समय में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

105. व्यापार में सुगमता प्रदान करते हुए, विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे ई-सीएलयू, ई-लाइसेंसिंग आदि को ऑनलाइन प्रदान करके हितधारकों की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, नागरिकों की सुविधा के लिए, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रावधानित सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। विभाग औद्योगिक और आवासीय प्लाटों के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अनुमोदन प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में भी है।

106. मेरी सरकार ने वर्ष 2023 में राज्य भर में सार्वजनिक खनन स्थलों की स्थापना करके बुनियादी स्तर पर सुधारों की शुरुआत की थी, जो पहले की नीतियों के मुकाबले एक क्रांतिकारी बदलाव था और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध करवा कर खनन क्षेत्र को जनता के लिए खोल दिया। इस वर्ष विभाग खनन क्षेत्र को और अधिक उदार बनाकर अगले पड़ाव के सुधारों की

शुरुआत करेगा, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में रेत और बजरी की आपूर्ति में भारी वृद्धि होगी, जिससे आम आदमी के लिए रेत और बजरी की कीमतें और कम हो जाएंगी।

107. मेरी सरकार वैध खनन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जनता को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए खनिज परिवहन वाहनों में जी.पी.एस डिवाइस लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और "पी.बी माइन्स इंस्पेक्शन ऐप"लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से अवैध खनन की रियल टाइम रिपोर्टिंग की जा सकेगी।

108. मेरी सरकार का राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसने देश में कृषि-वानिकी आधारित कार्बन वित्तपोषण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस पहल के तहत, राज्य ने 3,686 किसानों को उनकी कृषि भूमि पर किए गए वृक्षारोपण के लिए 45.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहुंचा कर लाभान्वित किया है।

109. वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। आज तक, मेरी सरकार द्वारा 2.92 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। पहले से चल रही "पंजाब हरियावल लहर" के हिस्से के रूप में, मेरी सरकार ने ट्यूबवेलों के आसपास लगभग 28.99 लाख पौधे लगाने में सफलता हासिल की है और 268 नानक बगीचियाँ और 46 पवित्तर वन तैयार किए हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता में अपना योगदान डाल रहे हैं।

110. मेरी सरकार पंजाब के नागरिकों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। पर्यावरणीय मुद्दों को समग्र और समयबद्ध तरीके से संबोधित करने के लिए राज्य पर्यावरण योजना और जिला पर्यावरण योजनाएं तैयार की गई हैं और योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों द्वारा कैप्टिव ट्रीटमेंट के स्थान पर अब अधिक ध्यान कपड़ा-रंगाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फार्मास्युटिकल इकाइयों जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार प्लांटों पर दिया जा रहा है ताकि

नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसी तरह, धान की पराली को खेतों से ले जाकर उपयोग को बढ़ाने के लिए, उद्यमियों और उद्योगों को बायो-मास पावर प्लांट, कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायो-इथेनॉल प्लांट और औद्योगिक बॉयलर में धान की पराली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूली उपायों के माध्यम से 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने के लिए डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन, चंडीगढ़ के सहयोग से राज्य का नेट ज़ीरो विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है। गणित और बिजली पर अद्वितीय गैलरी स्थापित करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को मजबूत करने के लिए पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कपूरथला के अपग्रेडेशन के लिए 26.90 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक प्रोजेक्ट लागू किया गया है।

111. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आबकारी एवं कराधान के राजस्व कलेक्शन में अच्छी वृद्धि देखी है। वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक जीएसटी कलेक्शन 22771.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की

तुलना में 12.51% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि वैट राजस्व 5.74% बढ़कर 7113.51 करोड़ रुपये हो गया। कुल मिलाकर, पी.एस.डी.टी कलेक्शन सहित कुल राजस्व 30056.2 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.85% की वृद्धि दर्शाता है। फरवरी 2025 तक आबकारी विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 14.37% की वृद्धि दर्शाते हुए 9266.68 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है।

112. मेरी सरकार ने आई.आई.टी हैदराबाद के सहयोग से राज्य में कर प्रशासन को स्वचालित करने और जीएसटी प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स टूल को सफलतापूर्वक लागू किया है। आई.आई.टी हैदराबाद द्वारा विकसित मॉड्यूल की शुरूआत ने परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है और कर संग्रह और अनुपालन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं।

113. कर चोरी को रोकने और अनुपालन बढ़ाने में राज्य खुफिया और निवारक इकाइयों और कर खुफिया इकाई के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। मानवीय और मशीनी दोनों तरह की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर, इन इकाइयों ने कर प्रणाली के भीतर

खामियों की सफलतापूर्वक पहचान की है। परिणामस्वरूप, एम.आई.पी.यू ने 143.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 139 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं।

114. "बिल लियाओ इनाम पाओ" योजना को आगे बढ़ाया गया है, जो कर अनुपालन बढ़ाने के लिए डीलरों से बिल प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु एक पहल है। इस पहल के परिणामस्वरूप, विभाग ने अनुपालन न करने वाले करदाताओं पर 2.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, और वर्ष में 83.19 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।

115. मेरी सरकार ने पुराने कर मुद्दों से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने और कम करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना को 16/08/2024 तक बढ़ा दिया है। इस पहल से 70,311 डीलर इस कार्यक्रम से सफलतापूर्वक लाभान्वित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन करदाताओं के लिए बकाया 867.28 करोड़ रुपये की छूट मिली है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 164.35 करोड़ रुपये का पुराना बकाया सफलतापूर्वक वसूल

किया है, जो लंबे समय से चली आ रही कर देनदारियों का निपटान करने में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का प्रतीक है।

116. मेरी सरकार प्रवासी भारतीयों को अपने-अपने गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रवासी भारती अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी भी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में 50% का योगदान दे सकते हैं, जबकि शेष 50% राज्य द्वारा दिया जाता है। जालंधर, लुधियाना, एसबीएस नगर, होशियारपुर नामक चार जिलों में दस प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एन.आर.आई भाईयों को आने वाले वर्षों में नए प्रोजेक्टों में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

117. आदरणीय सदस्यगण, यह सदन हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राजनीति का सच्चा प्रतिबिंब है। आपने हमारे संविधान में निहित इन मूल्यों को हमेशा बरकरार रखा है। अलग-अलग राजनीतिक संबद्धताओं के बावजूद, इस सदन का कोई भी सदस्य अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटा है और इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी सरकार की उपलब्धियाँ पंजाब के लोगों के प्रति

उसकी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाती हैं। मेरी सरकार सुदृढ़ सहयोग और साथ चलते हुए सभी के लिए न्याय की प्राप्ति एवं एक ज्ञानवान समाज की स्थापना करते हुए पंजाब को नई बुलंदियों पर ले जाने में विश्वास रखती है, जो सभी के लिए एक आदर्श साबित होगा।

118. मैं आशा करता हूं कि आपके विचार-विमर्श सार्थक रहेंगे तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी **'समृद्ध पंजाब'** की पुनः स्थापना के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।

जय हिंद